

छोटे कर्ज पर सख्ती बंद करें: सीतारमण

छोटी रकम पर कठोर वसूली को बताना अमानवीय

आरबीआई की निष्पक्ष व्यवहार सहिता लागू करने की अपील

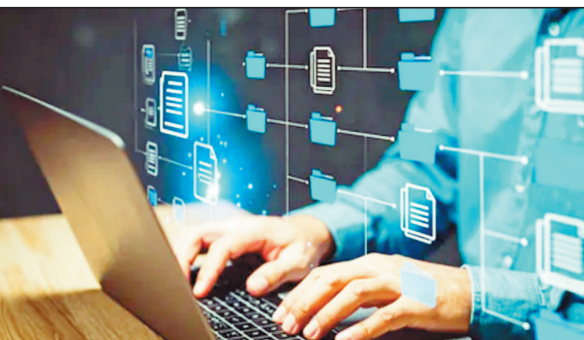
नई दिल्ली, 10 जुलाई.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एनबीएफसी संगोष्ठी 2025 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की ऋण वसूली प्रथाओं को निष्पक्ष, सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये प्रथाएं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निष्पक्ष व्यवहार सहिता के अनुरूप होनी चाहिए.

विशेष रूप से छोटी ऋण राशियों के मामले में कठोर वसूली उपायों से बचने का आग्रह किया, और ग्राहक गरिमा के महत्व को याद दिलाया. उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें 500 रुपये जैसी

छोटी राशि के लिए भी कठोर वसूली कार्रवाई की खबरें आती हैं, जिन्हें उन्होंने दल दहला देने वाली कहानियां बताया. उन्होंने कहा, विकास की होड़ ग्राहक कल्याण की कीमत पर नहीं आनी चाहिए. मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र

के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों का समर्थन करने में एनबीएफसी की भूमिका पर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि हर साल बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के लिए आवंटित पर्याप्त धनराशि अप्रयुक्त रह जाते हैं, जिन्हें बाद में नाबाई और सिडबी जैसे संस्थानों को हस्तांतरित कर दिया जाता है.

सीतारमण ने सवाल किया कि इन निधियों को वित्तीय संस्थानों को क्यों लौटाना जाना चाहिए, जबकि उन्हें जमीनी स्तर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एनबीएफसी, जो अक्सर अंतिम मील तक काम करती हैं, बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भागीदार के रूप में शामिल की जा सकती हैं. उन्होंने आरबीआई से इस साझेदारी को बिना विवेकपूर्ण मानदंडों को बाधित किए कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करने का भी आह्वान किया. मंत्री ने बताया कि जब धन नाबाई या सिडबी में वापस आता है और फिर से जारी किया जाता है, तो वितरण में छह से आठ महीने की देरी होती है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लक्षित लाभार्थियों को समग्र पर और लक्षित ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी की उपस्थिति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए.



टॉप 10 टेक मार्केट में शामिल होगा भारत: रिपोर्ट

बेंगलुरु-हैदराबाद तकनीकी बाजार की मांग में अग्रणी

भारत एशिया में तकनीकी प्रतिभा का केंद्र

नई दिल्ली, 10 जुलाई. कोलियर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 तकनीकी बाजारों में शामिल हो जाएगा, खासकर प्रतिभा उपलब्धता के मामले में. देश के शीर्ष छह शहर पहले से ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी प्रतिभा अधिग्रहण के लिए शीर्ष 10 की सूची में हैं. एशिया प्रशांत क्षेत्र एक वैश्विक टेक टैलेंट हब के रूप में

तेजी से उभर रहा है, जिसमें बेंगलुरु, टोक्यो और बीजिंग शीर्ष 10 में शामिल हैं. कोलियर्स इंडिया ऑफिस सर्विसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि भारत तकनीकी प्रतिभा का पावरहाउस है, जिसे कुशल प्रतिभा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता का समर्थन प्राप्त है. भारत के प्रमुख तकनीकी शहरों में एशिया प्रशांत क्षेत्र की कुल तकनीकी प्रतिभा का 69% हिस्सा है. बेंगलुरु और हैदराबाद, जो सबसे बड़े प्रतिभा समूहों की मेजबानी करते हैं, टेक लीजिंग गतिविधियों में अग्रणी हैं, और 2025 की पहली छमाही में पारंपरिक ऑफिस स्पेस की लगभग 50% मांग इन्हीं बाजारों से पूरी होगी.

भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रतिभाओं के लिए शीर्ष गंतव्यों में से एक है. बेंगलुरु और हैदराबाद भारत में पसंदीदा तकनीकी गंतव्य बने हुए हैं, जो कुशल प्रतिभाओं और एक परिपक्व तकनीकी पारिस्थिती तंत्र वाली वैश्विक तकनीकी कंपनियों को आकर्षित करते हैं. भारत के शीर्ष सात शहरों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उपयोगकर्ता ऑफिस स्पेस की मांग का आधार बने हुए हैं, जिसने पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक और फ्लेक्स स्पेस दोनों प्रकार के स्थानों में ग्रेड ए स्थान की मांग को बढ़ावा दिया है.

समाचार विशेष

उद्धव-राज के गठबंधन ने बड़ाई शिंदे की टेंशन



भाजपा को मिलेगा वोटर्स का अटेंशन!

इससे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत पर उपमुख्यमंत्री के दावे को नुकसान पहुंचने का खतरा है और मूल मराठी मतदाताओं के बीच उनकी स्थिति को चुनौती मिल सकती है. बाल ठाकरे के बेटे और भतीजे के एकजुट होने के बाद शिंदे को बाहरी और गद्दार का टैग हटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं उन्हें अपने क्षेत्र ठाणे में एक

बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य शहरी इलाकों में भी असर पड़ेगा. निकाय चुनाव पर होगा असर- गठबंधन की चर्चा नगर निकाय चुनावों में उठक रहे हैं, जिसमें उच्च दांव वाली बहुमुंबई नगर निगम (बीएमसी) भी शामिल है, जो शिंदे को चिंतित कर रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन उनके प्रभाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. सार्वजनिक अपील के बजाय पर्दे के पीछे की राजनीतिक चालों के लिए जाने वाले शिंदे को अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. उद्धव और राज का मिलन शिंदे के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में उनका प्रभाव कम होता दिख रहा है. महाराष्ट्र भाजपा के साथ शिंदे के रणनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन भाजपा के कई नेता उन्हें दीर्घकालिक साझेदार के बजाय अस्थायी सहयोगी के रूप में ही देखते हैं. इसके अलावा, उद्धव-

भाजपा को मिलेगा वोटर्स का अटेंशन!

इससे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत पर उपमुख्यमंत्री के दावे को नुकसान पहुंचने का खतरा है और मूल मराठी मतदाताओं के बीच उनकी स्थिति को चुनौती मिल सकती है. बाल ठाकरे के बेटे और भतीजे के एकजुट होने के बाद शिंदे को बाहरी और गद्दार का टैग हटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं उन्हें अपने क्षेत्र ठाणे में एक

पहुंचा सकता है. सार्वजनिक अपील के बजाय पर्दे के पीछे की राजनीतिक चालों के लिए जाने वाले शिंदे को अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. उद्धव और राज का मिलन शिंदे के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में उनका प्रभाव कम होता दिख रहा है. महाराष्ट्र भाजपा के साथ शिंदे के रणनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन भाजपा के कई नेता उन्हें दीर्घकालिक साझेदार के बजाय अस्थायी सहयोगी के रूप में ही देखते हैं. इसके अलावा, उद्धव-

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता होगी तेज

नयी दिल्ली, 10 जुलाई. भारतीय वाणिज्य मंत्रालय का एक दल प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ एक और दौर की वार्ता के लिए जल्द ही वाशिंगटन की यात्रा करेगा. एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत और पहले चरण, दोनों पर बातचीत होगी. यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि दल के अगले सप्ताह वाशिंगटन जाने की उम्मीद है. मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल समझौते पर वार्ता पूरी करने के बाद इस महीने की शुरुआत में ही वाशिंगटन से लौटा है. यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अतिरिक्त आयात शुल्क को एक अगस्त तक के लिए टाल दिया है.

भारत-आसियान व्यापार समीक्षा को मिले गति

नई दिल्ली, 10 जुलाई. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को आसियान के साथ मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा वार्ता में तेजी लाने की उम्मीद जताई. यह मुद्दा गोयल और उनके मलेशियाई समकक्ष टी जाफरुल अजीज़ के बीच बैठक में उठा.

गोयल ने कहा कि मलेशिया आर्थिक मामलों पर आसियान से भारत का स्थायी समन्वयक है. मंत्रियों ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा और चुनौतियों पर चर्चा की. गोयल ने निष्पक्ष व्यापार और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ चर्चा में तेजी लाने की बात कही. उन्होंने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीडीए) पर भी आगे की चर्चा की.

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समीक्षा वार्ता धीमी गति से चल रही है. भारतीय उद्योग लंबे समय से समझौते की समीक्षा की मांग



कर रहा है. भारत एक उन्नत समझौते की तलाश में है, जो द्विपक्षीय व्यापार में मौजूदा विषमताओं को दूर कर इसे अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाएगा. आसियान के सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं. भारत और आसियान के बीच वस्तुओं में मुक्त व्यापार समझौता 2009 में हस्ताक्षरित हुआ था और जनवरी 2010 में लागू हुआ. अगस्त 2023 में, दोनों पक्षों ने 2025 तक मौजूदा समझौते की पूरी समीक्षा की घोषणा की थी.

हीरो मोटोकॉर्प में नई शीर्ष नियुक्ति

नयी दिल्ली, 10 जुलाई. हीरो मोटोकॉर्प ने कौशल्य नंदकुमार को तत्काल प्रभाव से उभरती हुई व्यावसायिक इकाई का मुख्य कारोबार अधिकारी नियुक्त करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की. कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इस भूमिका में वह कार्यकारी चेयरमैन पवन मुजाल के अधीन काम करेंगे.

इसमें कहा गया, कौशल्य नंदकुमार के पास मोटर वाहन, इलेक्ट्रिक परिवहन, डिजिटल इनोवेशन और सामाजिक प्रभाव क्षेत्रों में लगभग दो दशकों का अनुभव है. कौशल्य नंदकुमार, स्वदेश श्रीवास्तव की जगह लेंगे जिन्होंने दोपहिया वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी से इस्तीफा दे दिया है.

भारत को मिली स्टारलिनक की रफ्तार

सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली, 10 जुलाई. एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिनक को भारत में अपनी सेवा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इ-न-स्पेस) से बुधवार को मंजूरी मिल गई है. यह अंतिम नियामक बाधा थी, जिससे स्टारलिनक के लिए देश में वाणिज्यिक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. मंजूरी के बाद, स्टारलिनक को अब सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करना होगा और अपनी सेवाओं के लिए जमीनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा. दूरसंचार विभाग सुरक्षा अनुपालन पूरा करने के लिए कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम देने को



तैयार है. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्टारलिनक देश में कुछ ही महीनों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है. स्टारलिनक ने भारत में वीसेट प्रोवाइडर्स के साथ पहले ही व्यावसायिक समझौते किए हैं, जो विशेष रूप से सीमित स्थलीय कनेक्टिविटी वाले स्थानों के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट समाधान

प्रदान करते हैं. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले हफ्ते ही पुष्टि की थी कि स्पेसएक्स की स्टारलिनक सेवा के भारत में प्रवेश के लिए सभी आवश्यक जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई हैं. स्टारलिनक मुख्य रूप से अंतरिक्ष वाले अपने 6,750 से अधिक सैटेलाइट के नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है.

भारत बनेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सरकार की प्राथमिकता: मल्होत्रा

नई दिल्ली, 10 जुलाई. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत स्वच्छ परिवहन के अपने मिशन पर सही राह पर है. इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक में मल्होत्रा ने बताया कि पीएम ई-ड्राइव और फेम-ड्रूज जैसी योजनाएं इस प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं. ईवी रेट्रोफिटिंग और टोल टैक्स छूट जैसी नीतियां परिवहन को सुलभ व टिकाऊ बनाती हैं. उन्होंने जोर दिया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि जलवायु लक्ष्यों, आर्थिक



मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है. मंत्रालय द्वारा विकसित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों को अब हरित ऊर्जा और ईवी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे लागत व उत्सर्जन कम होगा, और भारत की परिवहन स्थिति मजबूत होगी. मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस का वैश्विक केंद्र बनने की कगार पर है. उन्होंने हितधारकों से सुरक्षित, समावेशी और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी परिवहन भविष्य विकसित करने का आग्रह किया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सममेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792) रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर, बंगला, हैदराबाद रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031 फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अंतर्गत सूचना				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	106118189	होम लोन	14.06.2025	5,74,739.88/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. गोविंद विक्रम 2. ज्योति गोविंद				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	90264619	होम लोन	30.06.2025	8,34,887.72/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. ज्ञान सिंह अंसल 2. संतोष बाई				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	106078286	संपत्ति के बदले ऋण	09.06.2025	6,08,348.40/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. नेन सिंह 2. लैला बाई				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	125064038	संपत्ति के बदले ऋण	21.06.2025	6,32,644.21/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. तेज सिंह सौंधिया 2. कालू सिंह सौंधिया 3. पार्वती बाई				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	115643774	होम लोन	25.06.2025	4,84,561.88/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. राजेंद्र सिंह 2. गुंजा सोलंकी				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
6	115643774	होम लोन	25.06.2025	4,84,561.88/-

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सममेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबन्धित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सममेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देव राशि वसूलने के लिए उक्त उल्लिखित बैंक संपत्तियों के विरुद्ध एएएफआईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सममेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत विक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुविधित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 11.07.2025
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सममेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)